सम्पर्क सहयोग संस्कार सेवा समर्पण

भारत विकास परिषद् द्वारा निर्धन छात्र–छात्राओं की निशुल्क शिक्षा हेतु राष्ट्रीय परियोजना का प्रारूप

Draft of National project of *Bharat Vikas Parishad* for free education of needy and deprived children

Submitted to -

Ad. Gajendra Singh Sandhu
National President
Bharat Vikas Parishad
M. N.: 9412136841
E.: advgssandhu15@gmail.com

Sh. Kuldeep Ji
Prant Sewa Pramukh
Meerut Prant
M. N.: 9412784860
E.: skhera.adv@gmail.com

Subhash Khurana
Pranteeya Margdarshak
Bharat Vikas Parishad (U.P. West)
M. N. 9897490111
E.: sckhurana2012@gmail.com

Index

1. प्रमाणीकरण

2. प्रोजेक्ट टीम

3. आभार

4. राष्ट्रीय परियोजना का उद्देश्य, कठिनाईयाँ एवं निवारण

5. वर्तमान में विभिन्न शाखाओं द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास

6. प्रयासों के परिणामों का विश्लेषण

7. स्रोतों का विवरण (bibliography)

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रोजेक्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा मे ''झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कूडा बीनने को मजबूर'' सुविधाविहीन एवं निर्धन बच्चों की परिस्थितियों व शैक्षणिक अनुपलब्धता के संदर्भ में भारत विकास परिषद् द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित ''निर्धन छात्र–छात्रा शिक्षा प्रोजेक्ट'' के अंतर्गत समस्त देश भर में फैले विभिन्न क्षेत्रीय व प्रान्त स्तरीय शाखाओं को समुचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व दिशा निर्देश देकर राष्ट्र व मानवता के हित में संगठित व प्रभावशाली रूप से कार्य करने के लिए योजना बनाकर निर्णय लेने पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिए गए सभी विचार एवं विवरण राष्ट्रीय हित में प्रस्तुत किए गए है एवं किसी की आलोचना अथवा निन्दा करने का कोई उद्देश्य नही है। इसमें व्यवहारिक अनुभवों का प्रयोग करके तथ्यों का मूल्यांकन किया गया है।

प्रोजेक्ट टीम

सुभाष खुराना
पूर्व प्रा. अध्यक्ष
एवं प्रा. मार्गदर्शक
सदस्य माधव शाखा
मो. नं. – 9897490111

लवलीन गुप्ता
मार्गदर्शक
माधव शाखा, हापुड़
मो. नं. – 9837021105

सुरेश केडिया
मार्गदर्शक
माधव शाखा, हापुड़
मो. नं. – 9837487654

श्रीमती शालिनी माहेश्वरी
पूर्व महिला संयोजिका
माधव शाखा, हापुड़
मो. नं. – 8923363511

कपिल सिंघल
अध्यक्ष
माधव शाखा, हापुड़
मो. नं. – 9897029999

सुधीर गुप्ता
सचिव
माधव शाखा, हापुड़
मो. नं. – 8171000572

मुकुल जिंदल
कोषाध्यक्ष
माधव शाखा, हापुड़
मो. नं. – 9897592842

विनोद गुप्ता
क्षेत्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ
माधव शाखा, हापुड़
9837218618

श्रीमती पारूल गुप्ता
महिला संयोजिका
माधव शाखा, हापुड़
8171000580

श्रीमती नीलम खुराना
कार्यक्रम संयोजिका
माधव शाखा, हापुड़
9760099525

नरेश गर्ग
प्रान्तीय चेयरमैन
माधव शाखा, हापुड़
6395601648

श्रीमती नीलम गर्ग
प्रकल्प संयाजिका
माधव शाखा, हापुड़
8077629204

अमित सिंघल
जिला संयोजक
जनपद हापुड
9412219269

इ. अरूण त्यागी
प्रान्तीय संयोजक
माधव शाखा, हापुड
9891887474

पंकज गर्ग
जिला कोडिनेटर
माधव शाखा, हापुड
9897013904

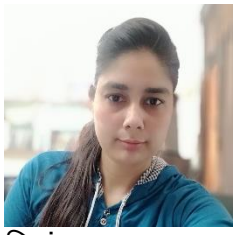

प्रियंका यादव
प्रकल्प समन्वयक
मिनीलैण्ड कान्वेण्ट स्कूल, हापुड

आभार

उपरोक्त प्रोजेक्ट के तैयार करने हेतु मैं माधव शाखा, हापुड़ के संस्थापक श्री नानक चंद जी क्षेत्रीय विभाग प्रमुख, मेरठ प्रान्त, प. उ. प्र. प्रान्त के अध्यक्ष श्री पंकज सक्सैना, सचिव श्री नरेन्द्र शर्मा, प्रा. वित्त सचिव श्री कवित बंसल एवं प्रा. महिला संयोजिका श्रीमती मुक्ता अग्रवाल, मेरे मार्गदर्शक सी. ए. अनिरूद्ध अग्रवाल, बहन श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती इन्दु वार्ष्णेय तथा विशेष रूप से माननीय एड. सुनील खेडा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का आभारी हूँ जिन्होंने हमें यह प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित किया।

मैं माधव शाखा के अध्यक्ष श्री कपिल सिंघल एवं समस्त सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। इस कार्य के लिए मिनीलैण्ड कान्वेण्ट स्कूल का विशेष सहयोग एवं प्रोत्साहन मिला, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

राष्ट्रीय परियोजना का उद्देश्य, कठिनाईयाँ एवं निवारण के उपाय

यह एक सर्व विदित कटु सत्य है कि निर्धन क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव एक वैश्विक समस्या है। यद्यपि इस क्षेत्र में लगभग सभी देशों की सरकारे, यूनिसेफ एवं अनेको एन. जी. ओ. निरन्तर कार्य कर रहे है पर न तो इनका ठोस परिणाम सामने आता है और न ही इस समस्या से युद्ध स्तर पर जूझा जा रहा है। यह प्रयास ''ऊँट के मुँह में जीरा'' के समान साबित हो रहे है।

जब पालियों, चेचक, अधंत्व व अन्य महामारियों के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होकर उनका निवारण कर सकता है तो वही एकजुटता इस समस्या के विरूद्ध क्यों नही दिखाई देती ?

इसमें आने वाली कठिनाइयों व निवारण पर परिचर्चा करके भारत विकास परिषद् एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में अंगीकार करने पर विचार करने का प्रयास करें, यही मेरा भगीरथ प्रयास है।

"An AIMLESS life is always a miserable life. Everyone of you should have an aim. But do not forget that the quality of your aim will depend the quality of your life. Your aim should be high and wide, generous and holistic; this will make your life precious to yourself and to others."
The education of human being should begin at birth and continue throughout his life.

The Mother
"on Education"

वर्तमान में विभिन्न शाखाओं द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास

पश्चिमी उत्तर प्रदेश शाखा में लगभग नौ शाखाएँ इस दिशा में कार्य कर रही है जिससे लगभग 162 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं जोकि एक अनुकरणीय कार्य है परन्तु अनुमान के अनुसार पूरे देश में हमारी मात्र 15% शाखाएँ इस दिशा में कार्य करती है। राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों से ही सही प्रतिशत का आंकलन हो सकता है यह एक सांकेतिक सूचना है। कुछ शाखाएँ लंबे समय से पूरे मनोयोग से कार्य कर रही है, जिनमें हापुड़ की माधव शाखा वर्ष 2009 से निरन्तर इस दिशा में कार्यरत है एवं इसे शीघ्र ही अपने विद्यालय भवन मे भारत विकास परिषद् विद्यालय के रूप में प्रकाशित करने जा रही है।

हापुड़ माधव शाखा के इस शिक्षा प्रकल्प की प्रारम्भिक झलकियां –

प्रकल्प का शुभारम्भ – रेलवे पार्क, हापुड़, वर्ष – 2009

मा. नानक चंद जी विभाग सेवा प्रमुख (मेरठ विभाग)
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (संस्थापक – माधव शाखा) बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए।

राष्ट्रीय पर्व का आयोजन

शैक्षिणक गतिविधियाँ

भारत विकास परिषद
माधव विद्यालय हापुड़

सम्पर्क
सहयोग
संस्कार
सेवा
समर्पण
हार्दिक शुभकामनायें
भारत विकास परिषद् हापुड़ माधव शाखा
स्थायी प्रकल्प ''माधव निर्धन छात्र-छात्रा शिक्षा''
कक्षा 6 की माधव कन्याएँ
देवी रुप सज्जा में माधव कन्याएँ
शाखा की अन्य गतिविधियां
शाखा के सांस्कृतिक आयोजन
हमारा आगामी स्थायी प्रकल्प
''माधव मूक बधिर शिशु शिक्षा व प्रशिक्षण केन्द्र''
देवेन्द्र महेश्वरी
अध्यक्ष
मो0 09412121237
सुरेश कुमार केडिया
सचिव
मो0 09837487654
राजीव कुमार गर्ग
कोषाध्यक्ष
मो0 09897011892
श्रीमती शालिनी महेश्वरी
महिला संयोजिका
मो0 08923363511

भारत विकास परिषद् हापुड़ 'माधव' शाखा
'' स्थायी प्रकल्प-निर्धन छात्र-छात्रा शिक्षा''
दीक्षा समारोह
16/06/2013 13:05

आवश्यक सामान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम

माधव शिक्षा प्रकल्प का पिछली वर्षों का कुछ रिकार्ड

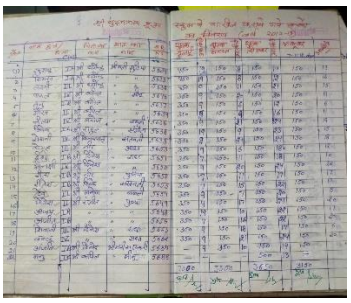

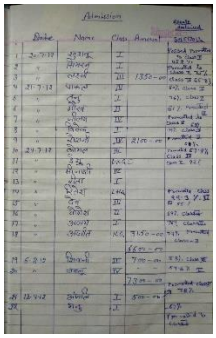
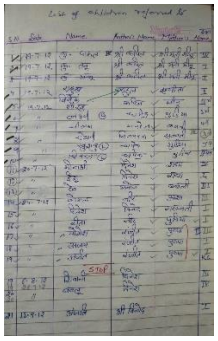
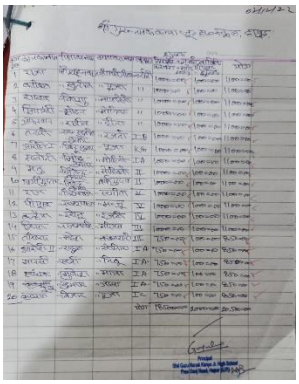

प्रारम्भ वर्ष 2009 छात्र/छात्रा संख्या – 92
निरन्तर जारी
वर्ष 2019–20 व 2020–21 में बन्द रहा। (कारण कोविड विभीषिका)
वर्ष 2022–23 पुनः प्रारम्भ, छात्र/छात्रा संख्या – 23, चिन्हित – 27
वर्ष 2023–24 वर्तमान सं. – 27, लक्ष्य – 30
वर्ष 2024–25 वर्तमान सं. – 24, लक्ष्य – 40
अभी तक लाभान्वित संख्या – छात्र 426
छात्राएँ 412
योग –838
उपरोक्त विवरण सेवा दिशा 2024 एप में अपलोड कर दिया गया है।

प्रयासों के परिणामों का विश्लेषण

यदि हम शैक्षणिक स्तर को देखे तो निम्न स्तर का कारण अधिकांशतः सामाजिक व आर्थिक रूप से उस वर्ग का पिछड़ापन है जोकि अविकसित झुग्गी झोपडियों मे रहते है। इनमें से अधिकांश लोग अपने मूल निवास के स्थानों से पलायन करके रोजगार की खोज में कस्बों व शहरों में बस जाते है। अधिकांश शहरों मे स्लम जनसंख्या कुल जनसंख्या के 10 से 15 प्रतिशत होती है। ये अनुसूचित जाति, जन–जाति व अन्य पिछडे वर्ग से संबंधित होते है। (Rao, Rani and Murty, 1977: 3; Naidu, 1978 : 303, Singh 1986: 35; Pati and Mohanty 1989:46, DeSouzza1981:175) इन्ही कारणों से वर्ष 1991 में हमारे देश के नगरीय क्षेत्रों की अनुमानित 10% जनसंख्या स्लम की निवासी पाई गई जबकि देश में साक्षरता दर 52.11% थी इनमें से स्लम में साक्षरता दर मात्र 19% थी यद्यपि वर्तमान में निरक्षरता दर विभिन्न राज्यों में न्यूनतम 66.4 व अधिकतम 93.91 है। शहरों में स्लम में वृद्धि वैश्विक स्तर पर हो रही है और साक्षरता की समस्या भी बढ़ रही है। स्लम में बच्चों को पढ़ाई में बाधक अन्य समस्याएँ, जैसे घर का वातावरण, सर्वत्र आच्छादित गंदगी, शौचालयों का अभाव, स्वच्छ जल, महिलाओं के अलग शौचालय न होना, चिकित्सालय उपलब्ध न होना शामिल है। कम स्थान पर अधिक छोटे–छोटे जनसंख्या का अधिक घनत्व, गन्दी नालियां व कभी सफाई न होने वाले क्षेत्र बीमारियों व प्रदूषण से ग्रस्त होते है। स्लम मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते है। ऐसे में जो बच्चे किसी सहायता से शिक्षित हो जाये तो यह उनकी विलक्षण क्षमता का परिचायक होता है। निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 का लाभ अधिकांशतः इन बच्चों को नही मिल पाता जिसका कारण माता–पिता को जानकारी न होना, मूलभूत प्रमाण पत्र यथा आधार कार्ड, आय व निवास का

प्रमाण पत्र, वोटर आई. डी. कार्ड का न होना। मुख्यतः शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इन क्षेत्रों में जाकर अभिभावकों को जागरूक करके इन बच्चों का प्रवेश प्राइवेट विद्यालयों मे नही कराया जाता। वस्तुतः इस योजना का लाभ सक्षम, अपात्र एवं पहुँच रखने वाले लोग उठाते है जोकि बच्चों को स्वयं पढ़ाने में पूर्णतय सक्षम है। इस योजना में अनाधिकृत रूप से मिश्रित भष्टाचार भी एक मुख्य कारण है।

इसके दुष्परिणाम के रूप में निम्न बातों को बढ़ावा मिलता है –

1. बाल श्रम (Child labour)
2. कुसंगति में पड़कर नशाखोरी, ड्रग्स जैसे कई व्यसन सीखना।
3. चोरी–चकारी व अन्य बाल अपराध करना, जुआ खेलना आदि।
4. शिक्षा सं वंचित कन्याओं का बाल–विवाह
5. मिशनरी संस्थाओं द्वारा धर्मान्तरण का प्रयास करना व लोभ–लालच सुविधा देकर धर्मन्तरण करना।
6. अशिक्षित कन्याओं को लव–जेहाद जैसे अभियानों का शिकार बनाना।
7. नाबालिंग बच्चियों का विवाह

यहां यह भी कहना उचित नही होगा कि माता–पिता का दृष्टिकोण भी बदला जाना आवश्यक है। अनेक अभिभावक लडकियों को पढ़ाना नही चाहते और जल्दी उम्र में शादी कर देते है क्योंकि पढ़–लिख जाने के बाद भी संभ्रांत समाज इन्हें नही अपनाएगा एवं जातीयता, समाज का सामाजिक दृष्टिकोण व अभिभावकों की गरीबी के कारण उनकी बेटियों को पढ़ाई के बावजूद संभ्रांत घरों में नही अपनाया जाता। खराब पारिवारिक परिस्थिति व अशिक्षा के कारण लगभग 62% नाबालिंग कन्याएं विवाहिता हो जाती है।

सरकारी योजनाएं अच्छी है लेकिन उनका अनुपालन त्रुटिपूर्ण ढंग से होता है। अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक संस्थाओं को ठोस एवं व्यवहारिक रूपरेखा बनाकर इस समस्या का निवारण करना होगा। इसमें भारत विकास परिषद् की ''ग्राम्य विकास एवं मलीन बस्ती अधिग्रहण योजना'' का समन्वय करके सम्पूर्ण स्लम को अंगीकृत करना होगा जिसमें धर्म, जाति, आयु, वर्ण, लिंग भेद को भुलाकर अभिभावकों को विश्वास में लेना होगा एवं बस्ती में निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाए –

1. स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करना।
2. उनकी आयु के हिसाब से कक्षा का निर्धारण।
3. उन कारणों को ढूँढना जिससे बच्चे पढ़ाई से वंचित है।
4. बस्ती में संबंधित पार्षद की सहायता से स्वच्छता एवं हैण्डपम्प लगवाने सुनिश्चित करना पानी की टकियां लगाना।
5. प्रशासन की सहायता से बस्ती के निकट ही सुलभ शौचालय बनवाना।
6. तरह–तरह के नशेबाजी यथा एल्कोहल, जुआ आदि से बचाना।
7. बच्चों को बाल श्रम से रोकना।
8. माता–पिता के मन में बच्चों को पढाने की इच्छा जागृत करने से ये सभी कार्य सुलभ हो जाएगे।
9. भारत विकास परिषद् खुर्जा के उदाहरण के सापेक्ष शाखाओं द्वारा अपना विद्यालय खोलना।

कुछ अन्य कार्य जैसे कि जिनका राशन कार्ड नही है या अन्य प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता करना, बेरोजगार पिताओं को रिक्शा आदि का ऋण प्रदान करना तथा माताओं को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना शामिल है जैसे कि हमारी कुछ शाखाएं हर प्रान्त मे ये कार्य कर रही है।

The Right to Education:

The right to education is recognised as a human right by the United Nations and is understood to establish an entitlement to free, compulsory primary education for all children, an obligation to develop secondary education accessible to all children, as well as equitable access to higher education, and a responsibility to provide basic education for individuals who have not completed primary education.

In addition to this access to education provisions, the right to education encompasses also the obligation to eliminate discrimination at all levels of the educational system, to set minimum standards and to improve the quality of education.

Acknowledgement

This is stated as per the 86th Constitution Amendment Act added Article 21 A. The Act, one of the flagship programmes in the 100-day agenda of the UPA government, also earmarks 25 per cent seats to weaker sections in private schools.

Relevance of the Right in Indian Context:

For those households with incomes below the official poverty line, the only hope for a future lies in education and resultant empowerment. According to the Government's own data, such households account for 27.5 per cent of India's one billion-plus population.

Independent research and CRY's own experience shows that the number of poor in India is closer to 70 per cent – those for whom day-to- day incomes barely cover living expenses. For this majority of Indians, the Constitutional Amendment in 2001 came with the promise that this liberal democracy will actually assume responsibility for all its citizens.

Some Important Facts and Figures:

Latest government estimates show 70 million children are out of school. This category largely comes from India's poorest – those who cannot and should not be forced to pay for schooling. Estimates show that the private education sector is valued at $40 billion (Rs 160,000 crore) in India. The HRD Ministry needs to get Section 25 of the Companies Act amended for this.

Acknowledgement

1. This is stated as per the 86th Constitution Amendment Act added Article 21 A. The Act, one of the flagship programmes in the 100-day agenda of the UPA government, also earmarks 25 per cent seats to weaker sections in private schools.

2. C.R.Y.

3. The above data note claimed as up to date/(2021-22').

Millions of the world's poorest urban children are more likely to die young and less likely to complete primary school than their rural peers—UNICEF

New York, 27 November 2018 – The poorest urban children in 1 in 4 countries* are more likely to die before their fifth birthday than the poorest children in rural areas. And the poorest urban children in 1 in 6 countries are less likely to complete primary school than their counterparts in rural areas, according to a new UNICEF report released today.
The report, *Advantage or Paradox: The Challenge for children and young people growing up urban* reveals that not all children in cities benefit from the so-called 'urban advantage' – the notion that higher incomes, better infrastructure, and proximity to services grant urban dwellers better lives. Instead, urban inequality, urban exclusion, and urban challenges to well-being, such as environmental and health hazards, can together result in an 'urban paradox' where many urban residents – including children – miss out and suffer more severe deprivations than their rural peers.

"Children should be a focus of urban planning, yet in many cities they are forgotten, with millions of children cut-off from social services in urban slums and informal settlements, and exposed to environmental or health hazards due to overcrowding," Chandy added. "Implementing solutions to urban development and planning is crucial to arrest these social and economic disparities."

In the absence of innovative ways of supporting the urban poor, inequity in childhood outcomes may widen and an increasing number of urban children will be shut out of overall progress.

The report calls for a number of actions from urban authorities and the global community:

- Making urban areas an integral part of programming for children, including the most vulnerable.
- Developing the capacities of inclusive urban planning at all levels of government—national, regional and local.
- Accelerating the development of urban systems of infrastructure and services to keep pace with current trends of rapid urbanization.
- Finding new solutions for mobilizing financial resources to improve urban systems and increase equity within urban areas.

Investing in better data and better use of existing data to understand the full extent and dimensions of urban inequity.

Acknowledgement**

*** Studies and survey UNICEF*

UNICEF partnerships

The world's largest challenges need the world's largest team.

UNICEF works day in and day out, in some of the world's toughest places, to protect children's rights and safeguard their futures. On the ground in over 190 countries and territories, we reach more children and young people than any other international organization. But we can't do it alone.

UNICEF unites with the public sector, private sector and civil society to improve children's health, nutrition, education and protection. Our individual supporters help by donating, volunteering or being advocates for children and young people in their communities.

Entirely reliant on voluntary contributions, we bring more than 70 years of field-tested expertise, a network that spans the globe, a passion for innovation, and a commitment to making every dollar count.

Acknowledgement**

*** Studies and survey UNICEF*

निर्धन एवं वंचित बच्चों के घर भारत विकास परिषद्

मलीन बस्तियों (slum) में रहने वाले लोग सिर्फ शिक्षा के मोर्चे पर ही नही, बल्कि और भी कई मोर्चों पर दुश्वारियों का सामना करना रहे हैं। इन बस्तियों में जीवन बसर कर रहे लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, पानी और बिजली से भी वंचित हैं और शिक्षा का स्तर (education level) सबसे निचले पायदान पर है। लिहाजा, यहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए भारत विकास परिषद् संस्था आगे आई है।

भारत में मलीन बस्तियों की तस्वीर निराश करने वाली है। यहां शैक्षिक, आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का बच्चों के विकास पर गहरा असर पड़ा है। यहां के बच्चे हर मायने में आम बच्चों की अपेक्षाकृत पिछड़ेपन का शिकार हैं। यहां, जिन बच्चों के माता–पिता निरक्षर हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति कम जागरूक हैं, लेकिन वर्तमान में निरक्षर अभिभावक भी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाते जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ परिवर्तन अधिकांश शहरों में देखने को मिल रहा है। जहां ऐसी कई ऐसी लड़किया है जो पढ़ना चाहती है, लेकिन वो आर्थिक तौर पर काफी कमजोर हैं। लिहाजा, भारत विकास परिषद् टीम इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा मुहैया कराकर उनके सपनों को पंख लगा रही है।

वैसे तो मलीन बस्तियों में रहना ही अपने आप में काफी पीड़ादायक है। इस अस्तियों के बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं और यहां की तस्वीर बहुत ही भयावह है। शहीरी मलीन बस्तियों में रहने वाले लोग सिर्फ शिक्षा के मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि और भी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन बस्तियों में जीवन बसर कर रहे लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, पानी और बिजली से भी वंचित हैं और शिक्षा का स्तर सबसे निचले पायदान पर है। खासकर, भारत विकास परिषद् जहां बच्चों को स्कूल जाने एवं पढ़ाने की पहल के ''सर्व शिक्षा अभियान'' के तहत ''सब पढ़ो सब बढ़ो'' का नारा दे रही है।

इन सबके बीच ये बदतर तस्वीर चिंतित करने वाली है, हालांकि, सामाजिक संगठन इस मामले में आगे आ रहे हैं। इन्ही में से एक नाम है हापुड़ की भारत विकास परिषद् माधव शाखा जो मलीन बस्तियों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने की सराहनीय पहल कर रहे हैं। वो उन बच्चों का स्कूलों में दाखिला करा रहे है, जिनके अभिभावक शिक्षा खर्च वहन नही कर सकते। उन्होंने छह कन्याओं को गोद भी लिया है। अनेको छात्र/छात्राएं नर्सरी से आगे जाकर कक्षा 12 पास कर चुके हैं।

मलीन बस्तियों में रहने वाली रजनी कहती हैं वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लिहाजा, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मुहैया कर सकते। वहीं मुस्कान आंखों में आसू लिए अपने सपने की बुनियाद को मजबूत कर रही हैं। वो भी आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। पिता की मृत्यु के बाद मां पर भाई बहन के भरण–पोषण और शिक्षा–दीक्षा दिलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन मां मजबूर हैं, लिहाजा भारत विकास परिषद् टीम इन बच्चों का सहारा बनी हैं।

स्रोत (Bibliography)

1. “Education amongst slum children” by M. D. Patil
2. “On Education” by The Mother Sri Acerobindo Ashram
3. “बच्चे – मानवता की महानतम सम्पत्ति’’ लेखक स्वामी रंगनाथनन्द (श्री रामकृष्ण विवेकानन्द – वेदान्त साहित्य)
4. https://www.slideshare.net
5. https://educationworld.in
6. https://hindrise.org
7. http://penpaper.blogspot.com
8. निजी अनुभव

निष्कर्ष

इस सेवा कार्य से मलीन बस्तियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता, नशाखोरी की आदतों से बचाव, धर्म परिवर्तन, भिक्षावृत्ति, चोरी– झीना झपटी में कमी होने जैसे परिणाम सामने आए है एवं बच्चों को रोजगार में सहायता मिली है। संस्था द्वारा योग्य एवं परिश्रमी बच्चों को कक्षा 12 तक पढ़ाया जाता है तथा तदुपरान्त रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाता है।

इस क्षेत्र में ठोस कार्य करना, अन्य कार्यों की तरह ही मानवता व सच्ची राष्ट्र सेवा है। **अतः भारत विकास परिषद् में स्लम शिक्षा को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाय, ऐसी मेरी प्रार्थना है।** हमारी परिषद् प्रत्येक प्रोजेक्ट को मूर्तरूप देने में अनुभवी व पूर्ण सक्षम है। इस विषय पर चिन्तन मनन के उपरान्त उचित निर्णय लिया जाए।

६ वीं शताब्दी में मध्य भारत के एक राज्य के भर्तृहरि नामक महान कवि ने "नीतिशतकम्" नामक एक महान ग्रंथ लिखा है। उसके ७५ वे श्लोक में वह कहता है :

एके सत्–पुरुषाः परार्थ घटकाः
स्वार्थान् परित्यज्य ये।
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृताः
स्वार्थाविरोधेन ये।।
तेऽमी मानव–राक्षसाः पर–हितम्
स्वार्थाय निघ्नन्ति ये।
ये तु घ्नन्ति निरर्थकं पर–हितम्
ते के न जानीमहे।।

'कुछ सत्पुरुष होते हैं जो स्वयं को परहित के लिए समर्पित कर देते हैं। यहाँ तक कि वे स्व–हित का भी परित्याग कर देते हैं.....

इति

Project Prepared & Complied by –
Subhash Khurana
(Member Madhav Shakha Hapur)
Prantiya Adhyaksh (2014-15)